इब्राहिम अबूबकर और अन्य

बनाम

टेक चंद डौलवानी

इब्राहिम अबूबकर और अन्य

बनाम

कस्टोडियन जनरल ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी

इब्राहिम अबूबकर और अन्य

बनाम

यू. एम. मिर्चंदानी।

[पतंजलि शास्त्री सी. जे., मुखर्जी, दास,हसन और भगवती जेजे.]

निर्वासित संपत्ति प्रशासन अधिनियम (1950 का XXX1),

उपधारा 2 (घ) और (च), 7-किसी व्यक्ति को विस्थापित घोषित करने की कार्यवाही और उसकी संपत्तियों को खाली करने वाली संपत्तियां-

लंबित रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु प्रोसीडिंग्स-कार्यवाही में कमी-उत्तराधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की वैधता।

जहाँ एक मुसलमान जिसके खिलाफ निर्वासित संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के तहत,कार्यवाही की जाती है उसे निकासी घोषित करने के लिए और उसकी संपत्तियों को निकासी करने वाली संपत्तियों की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है जिसे निर्वासित घोषित नहीं किया जा सकता है।

उसकी मृत्यु के बाद एक निर्वासित, और उसकी संपत्ति जो उसकी मृत्यु पर मुसलमान कानून के तहत उसके उत्तराधिकारियों में निहित होने की घोषणा नहीं की जा सकती है।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 65/1953

सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा अपील

13 मार्च, 1953 को न्यायालय ने निर्णय से और

अभिरक्षक का 30 जुलाई, 1951 का आदेश नंबर 31-ए/जूडी में निकासी संपत्ति के जनरल। / 50.1952 की याचिका संख्या 247, अनुच्छेद के तहत एक याचिका 32 निधि के प्रवर्तन के लिए संविधान का मानसिक अधिकार, और विशेष अनुमति के लिए याचिका 1952

की अपील सं. 106 पर भी सुनवाई हुई।

सिविल अपील संख्या 65/1953

अपीलार्थियों और याचिकाकर्ताओं के लिए के. टी. देसाई।

सी. के. डाफ्टरी, सॉलिसिटर-भारत के लिए जनरल (पोरस)

ए. मेहता उनके साथ) याचिका में प्रतिवादी के लिए सं. 247।

10 अप्रैल 1953 न्यायालय का निर्णय

गुलाम हसन जे.-समझने के लिए और इसमें विचार के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदु की सराहना करें। मामले में, कुछ प्रारंभिक निर्धारित करना आवश्यक होगा

तथ्यः --

बॉमबे के निवासी अबूबकर अब्दुल रहमान को 16 दिसंबर, 1949 को बॉम्बे के अतिरिक्त राष्ट्रीय संरक्षक से अध्यादेश सं 1949 27 धारा 7 के तहत एक नोटिस प्राप्त हुआ कि कारण दिखाएँ कि कुछ विशिष्ट पेशेवरों में उनकी रुचि क्यों है संपत्ति को निर्वासित संपत्ति घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 11 जनवरी, 1950 को जारी एक और नोटिस में उन्हें कारण बताने की आवश्यकता थी कि उन्हें क्यों ऐसा घोषित नहीं किया जाना चाहिए। 8 फरवरी, 1950 को अतिरिक्त

अभिरक्षक ने फैसला किया कि अबूबकर एक निकासी नहीं था, लेकिन साथ ही उन्हें एक नया नोटिस जारी किया धारा 19 के तहत, उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि उसे खाली करने का इरादा रखने वाला क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए और अगले दिन, 9 फरवरी को उसी साक्ष्य के आधार पर उन्होंने अबू की आशयतन निकासी घोषणा की। लेकिन एक टेक चंद डोलवानी, पहली सूचना मेंट ने मामले को अभिरक्षक को अपील में ले जाया गया। प्रार्थना कर रहे हैं कि अबूबकर को एक निकासी घोषित किया जाए खाली करने वाला और वह इंपीरियल सिनेमा, उसका एक संपत्ति, उसे आवंटित की जाए।

अध्यादेश की अवधि 18 अक्टूबर, 1949 को समाप्त हो गई और इसे 1950 के गगग 1 अधिनियम (निर्वासित संपत्ति प्रशासन अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 17 अप्रैल, 1950 को लागू हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि यद्यपि अध्यादेश को धारा 58 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अध्यादेश द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कार्यवाहियों को ऐसा माना जाएगा कि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लिया गया अधिनियम मानो उस दिन अधिनियम लागू था जिस दिन कार्यवाही की गई।

अपील की सुनवाई 13 मई, 1950 को हुई थी, जब रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियाँ लायी गयी। अपील पर बहस की गई और अपील की गई आदेशों के लिए 15 मई तक के लिए स्थगित। 14 मई को अबू बेकर की मृत्यु हो गई और वे तीन बेटों और एक बेटी को छोड़ गए। मुस्लिम कानून के तहत बेटी को उसके उत्तराधिकारी के रूप में, बेटों का 2-7 वां हिस्सा मिलेगा। हालाँकि, आदेश 13 मई को दिया गया था। इस आदेश में उन्होंने प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि आगे की पूछताछ की जानी चाहिए और कि अबूबकर से 19 अगस्त को और पूछताछ की जाए, 1950. अपील की सुनवाई से स्थगित कर दी गई थी समय-समय पर और मार्च में अंतिम निपटान के लिए तय किया गया था 7, 1951. इस सुनवाई का नोटिस इब्राहिम को जारी किया गया था।

अबूबकर (बेटा) और हवाबाई अबूबकर (बेटी) जिनके पास अपने बीच 3/7 वें हिस्से का स्वामित्व था, मृतक के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में वे उपस्थित होंगे। याचिकाकर्ता, जो भारत के निवासी हैं-उनके दो भाई पाकिस्तान चले गए थे-दायर 26 फरवरी, 1951 को विविध याचिका संख्या 15 1951 का, पंजाब उच्च न्यायालय में प्रो के रिट के लिए निर्देश या आदेश के लिए कस्टोडियन

जनरल आगे बढ़ने से रोकेंगे अपील की सुनवाई या कोई आदेश देना मृतक को निर्वासित संपत्ति के रूप में। याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि अबूबकर की मृत्यु के बाद अभिरक्षक जनरल के पास अपील को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। याचिका को 24 मई, 1951 को खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय ने माना कि अभिरक्षक जनरल के पास अधिकार क्षेत्र था। अपील करने की अनुमति अनुदान कि गयी लेकिन उच्च न्यायालय ने कस्टोडियन जनरल की अपील की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई, जो 3 जुलाई, 1951 के लिए निर्धारित की गई थी, और निर्देश दिया कि कस्टोडियन जनरल को 23 जुलाई, 1951 तक अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। 3 जुलाई को कस्टोडियन जनरल ने अपील पर सुनवाई की और 30 जुलाई को जो अंतिम आदेशों के लिए निर्धारित तिथि थी, उन्होंने अबूबकर को एक निर्वासित और अपने समर्थक के रूप में घोषित किया। निकासी की गई संपत्तियों के लिए अधिकार।

6 अगस्त, 1951 को याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका दायर की।

(बॉम्बे हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 1951 की विविध याचिका संख्या 191)

कस्टोडियन जनरल के खिलाफ अदालत बॉम्बे, उक्त आदेश को

रद्द करने और दरकिनार करने के लिए और कस्टोडियन जनरल और स्थानीय कस्टोडियन को आदेश पर कार्रवाई करने या बॉम्बे में स्थित संपत्ति पर कब्जा करने का निर्देश देने के लिए प्रमाणपत्र के एक रिट के लिए याचिका दायर की। 4 अक्टूबर, 1951 को न्यायमूर्ति शाह द्वारा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को कस्टोडियन जनरल के खिलाफ कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और स्थानीय अभिरक्षक के खिलाफ याचिका पूर्व परिपक्व थी। उक्त आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में 5 अक्टूबर, 1951 को 1951 की अपील संख्या 88 दायर की गई थी। एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने लेखा रखने और संपत्तियों का निपटान नहीं करने का बीड़ा उठाया, जबकि संरक्षक जनरल ने लंबित रहने तक कब्जा नहीं लेने का बीड़ा उठाया।

अपील की सुनवाई। यह अपील 20 नवंबर, 1951 को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, लेकिन इसे पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए अनुमति दी गई थी क्योंकि वे ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते थे जो इस अदालत के फैसले के विपरीत हो। उस अपील को इस अदालत ने 26

मई, 1952 को खारिज कर दिया था। सामान्य निकासी संपत्ति 1)। इस अदालत ने फैसला सुनाया। केवल प्रारंभिक बिंदु है कि टेक चंद डोलवानी को अपील करने का अधिकार था लेकिन अधिकार क्षेत्र के बारे मे सवाल छोड़ दिया गया। संरक्षक जनरल को अबूबकर की संपत्तियों को निकासी समर्थक घोषित करें।

इसके समक्ष उठाया गया 30 जुलाई, 1951 का आदेश, उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बाद पारित किया गया इसलिए कि वह प्रश्न

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में निर्णय लंबित था। 1951 की अपील सं. 88 पहली/दूसरी तारीख को खारिज कर दी गई थी। जुलाई, 1952, मुख्य न्यायाधीश और गजेंद्र जे. गडकर द्वारा प्रारंभिक आधार पर कि उनके पास अभिरक्षक के आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जनरल का 30 जुलाई, 1951 को निधन हो गया। उन्होंने यह देखते हुए स्थानीय संरक्षक के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि वे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं कर सकते जो सीधे नहीं किया जा सकता था। 14 जुलाई, 1952 को उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की अनुमति के लिए एक याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

1952 की याचिका संख्या 105 विशेष अवकाश के लिए है। संरक्षक जनरल के आदेश के खिलाफ अपील अपीलीय पीठ के आदेश के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय दिनांक 1/2 जुलाई, 1952। 1952 की याचिका संख्या 247 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक स्वतंत्र याचिका है, जिसमें 30 जुलाई, 1951 के संरक्षक जनरल के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में। टेक चंद डोलवानी ने याचिका संख्या 105/1952 के खिलाफ कैविएट दायर किया है जबकि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की सुनवाई कस्टोडियन जनरल को नोटिस पर की गई है। इस याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि अध्यादेश और निकासी समर्थक संपत्ति प्रशासन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के सही निर्माण पर, अभिरक्षक जनरल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था अबूबकर की मृत्यु के बाद अपील पर सुनवाई करना, या उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को निकासी संपत्ति घोषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नही है। क्योंकि उसकी मृत्यु पर अपील को समाप्त कर दिया गया था और मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में विशिष्ट शेयरों में निहित थी। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि उक्त संपत्तियां 30 जुलाई, 1951 को या

अबूबकर की मृत्यु के बाद किसी भी समय निकासी संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती थीं, इसलिए अभिरक्षक जनरल के पास संपत्तियों को निकासी संपत्ति घोषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वास्तव में, मृतक की मृत्यु के बाद उक्त संपत्तियों में उसका कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था और न ही उसके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्तांतरण के किसी भी तरीके से अधिगृहीत की गयी थी।

30 जुलाई, 1951 के आदेश को अमान्य और निष्क्रिय मानकर चुनौती दी गई है कि कस्टोडियन जनरल क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 (1) के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन जनरल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की। कस्टोडियन जनरल के खिलाफ उपरोक्त आदेश से संबंधित मामले के रिकॉर्ड बुलाने और देखने के बाद उसी में प्रवेश करना और उसकी वैधता के प्रश्न में जाना और उसे अलग रखना। वे निषेध या आदेश या निर्देश या एक आदेश या एक रिट की भी मांग करते हैं जो कस्टोडियन जनरल, उनके सेवकों और एजेंटों को 30 जुलाई, 1951 के आदेश पर कार्रवाई करने या उसे लागू करने या उसे लागू करने के लिए कोई कदम या कार्यवाही करने से रोकने का निर्देश देता है।

हमने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर-जनरल को सुना और तब तक के आदेश सुरक्षित रखे जब तक कि हम डोलवानी को नहीं सुन लेते जो अपील करने के लिए विशेष अनुमति के आवेदन में कैविएटर थे। डोलवानी को व्यक्तिगत रूप से और उनके एजेंट के माध्यम से एक नोटिस दिया गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी पेश नहीं हुआ। हमने अभिरक्षक जनरल के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी और अनुच्छेद 32 के तहत अपील के साथ सुनवाई के लिए अपील को पोस्ट करने का निर्देश दिया। डोलवानी फिर से दिखाई नहीं दिया। और इसलिए हम एक सामान्य निर्णय द्वारा अपील और याचिका का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

हमारे सामने विचार के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह यह है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद निर्वासित घोषित किया जा सकता है और क्या मुस्लिम कानून के तहत उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में निहित संपत्तियों को उचित निर्वासित घोषित किया जा सकता है। उस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की स्थिरता के बारे में सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाई गई

आपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। उनका तर्क है कि वर्तमान मामले में मानसिक अधिकार के किसी भी उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कानून के अधिकार के बिना किसी भी संपत्ति से वंचित नहीं किया गया है। यह कहा जाता है कि संरक्षक जनरल, निस्संदेह एक एक्सप्रेस के तहत कार्य करने के लिए कथित है। वैधानिक अधिनियमन। हो सकता है कि उसने गलत आवेदन किया हो या कानून की गलत व्याख्या की या अधिकार क्षेत्र की धारणा या प्रयोग में कोई त्रुटि की, लेकिन यह मामले को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) के साथ पठित अनुच्छेद 31 (1) के दायरे में नहीं लाएगा। मुद्दा विवादास्पद है और हम इसे व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर कोई राय जैसा कि हम प्रस्तावित करते हैं

अपील (1953 की सिविल अपील संख्या 65) में 30 जुलाई, 1951 के अभिरक्षक जनरल के आदेश की वैधता की जांच करें, जो 1952 की याचिका संख्या 105 से विशेष अनुमति के लिए उत्पन्न हुई थी, न कि विशेष आदेश के लिए।

अनुच्छेद 32 के तहत याचिका। धारा 2 (डी) और (एफ) निष्कासन और निष्कासीत सम्पत्ति को परिभाषित करते हैं। जो इस प्रकार हैः ----

(घ) निकासि का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो भारत और पाकिस्तान के अधिराज्य या नागरिक अशांति या ऐसी अशांति के भय के कारण, 1 मार्च, 1947 को या उसके बाद छोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं। किसी राज्य में उन क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान के लिए जो अब भारत का हिस्सा हैं, या जो अब किसी भी स्थान पर निवासी है।

पाकिस्तान का हिस्सा और जो उस कारण से असमर्थ है व्यक्तिगत रूप से अपनी संपत्ति पर कब्जा, पर्यवेक्षण या प्रबंधन करें। उन क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में जहां यह अधिनियम पूर्व प्रवृत्त होता है, या जिनकी संपत्ति उक्त अधिनियम के किसी भी हिस्से में है। क्षेत्रों पर कब्जा करना, पर्यवेक्षण करना या बंद कर दिया गया है किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित या कब्जा किया जा रहा है, किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिकृत या प्रबंधित, या जिसके पास 14 अगस्त, 1947 के बाद, प्राप्त किया गया, खरीद या पूर्व के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया किसी में परिवर्तन, कोई अधिकार, ब्याज या लाभ ऐसी संपत्ति जिसे निर्वासित या परित्यक्त माना जाता है, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत संपत्ति

(च) बेदखल संपत्ति का अर्थ है किसी भी संपत्ति में जिसे निकालने वाले का कोई अधिकार या हित है (चाहे व्यक्तिगत रूप से

या न्यासी के रूप में या लाभार्थी के रूप में या किसी भी मामले में अन्य क्षमता), और इसमें कोई भी संपत्ति शामिल है

(1) जो किसी भी व्यक्ति द्वारा 14 अगस्त, 1947 के बाद प्राप्त किया गया हो

एक निर्वासित हस्तांतरण का कोई भी तरीका, जब तक कि ऐसा हस्तांतरण नहीं किया गया हो अभिरक्षक द्वारा पुष्टि की गई हो। वर्तमान काल लीव्स या हैस लेफ्ट का उपयोग निकासी की परिभाषा में और हैस का उपयोग परिभाषा में किया जाता है। निकासी संपत्ति के समर्थन में भरोसा किया जाता है

यह तर्क कि विधानमंडल का उद्देश्य इन प्रावधानों को लागू करना उनके कार्य को केवल एक जीवित व्यक्ति तक सीमित करना था। तर्क की यह पंक्ति यह अपने आप में किसी सम्मोहक बल का नहीं हो सकता है लेकिन यह शेष प्रावधानों से समर्थन प्राप्त करता है वह अधिनियम जिसके लिए आगे निर्देश किया जाएगा। तथापि, यहाँ यह इंगित किया जा सकता है कि खंड (च) (1) याचिकाकर्ताओं के मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि वे निकासी के बाद संपत्ति का दावा नहीं करते हैं

14 अगस्त, 1947 का दिन, हस्तांतरण के किसी भी तरीके से

लेकिन मुसलमान कानून के तहत उत्तराधिकार के अधिकार द्वारा। संपत्ति के उत्तराधिकार का अर्थ ओपेरा द्वारा हस्तांतरण है। कानून का गठन और उचित रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है हस्तांतरण का एक तरीका, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा तर्क दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से एक हस्तांतरण पर विचार करता है

धारा 7 निकासी संपत्ति की अधिसूचना को संदर्भित करती है। यह बताता है कि जहाँ अभिरक्षक यह राय है कि कोई भी संपत्ति निकासी संपत्ति है इस अधिनियम के अर्थ के भीतर, वह रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इस तरह से सूचना देने के बाद, और मामले की परिस्थितियों की अनुमति के रूप में मामले में ऐसी जांच करने के बाद, ऐसी किसी भी संपत्ति को निकासी संपत्ति घोषित करने का आदेश पारित कर सकता है।

नियम 6, जो शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया है अधिनियम की धारा 56 द्वारा प्रदत्त, धारा 7 के तहत जांच के तरीके को निर्धारित करता है और यह इस प्रकार हैः (1) जहाँ अभिरक्षक को अपने कब्जे में या अन्यथा इस सूचना से संतुष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति या उसमें कोई हित प्रथम दृष्टया निकासी संपत्ति है, वह ऐसी संपत्ति पर अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या किसी अन्य

व्यक्ति या व्यक्ति पर, जिसे वह संपत्ति में रुचि रखता है, प्रपत्र संख्या 1 में नोटिस जारी कराएगा।

(2) जहां तक संभव हो, नोटिस में उल्लेख किया जाएगा। जिन आधारों पर संपत्ति को निर्वासित संपत्ति घोषित करने की मांग की गई है और वह अधिनियम के अनुकूल दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करेगा जिसके तहत व्यक्ति दावा करता है। ऐसी संपत्ति का कोई भी अधिकार या उसमें हित एक निकासी होने का आरोप लगाया जाता है।

(3) सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, लेकिन यदि जो व्यवहार्य नहीं है, सेवा नियम 28 में प्रदान किए गए किसी भी तरीके से प्रभावी हो सकती है। (यह नियम प्रतिस्थापित सेवा के एक तरीके को संदर्भित करता है)।

(4) जहाँ एक सूचना विधिवत जारी की गई है, और पक्ष ने कारण दिखाने का आह्वान किया कि संपत्ति को निकासी संपत्ति क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहा सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर पेश होने पर, अभिरक्षक मामले की एकतरफा सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है और उसके सामने मौजूद सामग्री पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(5) जहाँ ऐसा पक्ष प्रकट होता है और नोटिस का विरोध करता

है वह तुरंत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अभिवचन के रूप में उसी तरीके से सत्यापित एक लिखित बयान दायर करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उसे निकासी क्यों नहीं माना जाना चाहिए और उसमें संपत्ति या उसके हित को निकासी संपत्ति के रूप में क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जांच या संपत्ति में रुचि रखने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति निर्वासित संपत्ति के रूप में घोषित होने पर, इस तरह के लिखित बयान का जवाब दाखिल कर सकते हैं। फिर अभिरक्षक, या तो उसी दिन या उसके बाद के किसी भी दिन, जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, उस साक्ष्य की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा, यदि कोई हो, जिसे पक्षकार कारण दिखाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है और उस साक्ष्य को भी प्रस्तुत कर सकता है जिसे पक्षकार ऊपर उल्लिखित रुचि रखने का दावा करता है।

(6) पूरा सबूत विधिवत दर्ज होने के बाद निर्धारण के लिए बिंदु, और उस पर निष्कर्ष संक्षिप्त कारणों के साथ नियमों के परिशिष्ट ए में प्रपत्र संख्या 1 इस प्रकार है निम्नलिखित हैः

जहाँ विश्वसनीय जानकारी है कि अभिरक्षक के पास यह अधिकार कि आप एक निर्वासित हैं प्रशासन की धारा 2 (घ) के खंड

(111) के अधीन आधारों के कारण निर्वासित संपत्ति अधिनियम में नीचे उल्लेख किया गया हैः और जहाँ आपको सुनना वांछनीय है इसलिए अब आपको दिखाने के लिए कहा जाता है। कारण (उन सभी भौतिक सबूतों के साथ जिन पर आप चाहते हैं) भरोसा करने के लिए) घोषित करने के आदेश क्यों नहीं पारित किए जाने चाहिए आप एक निर्वासित हैं और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्तिआपकी सारी संपत्ति निकासी के रूप में है ।

डिप्टी अभिरक्षक सहायक अगला महत्वपूर्ण खंड धारा 8 प्रासंगिक है। जिसका हिस्सा इस प्रकार हैः

(1) कोई भी संपत्ति जिसे खाली कराने वाली संपत्ति घोषित किया गया हो धारा 7 के तहत राज्य के संरक्षक में निहित माना जाएगा,

(क) निर्वासित व्यक्ति की संपत्ति के मामले में धारा 2 के खंड (घ) के उपखंड (प) में परिभाषित, उस तारीख से जिस दिन वह किसी स्थान को छोड़ता है या छोड़ता है। अब भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान के लिए एक राज्य; यदि हम धारा 8 में इसकी परिभाषा को प्रतिस्थापित करते हैं धारा 2 में दी गई निकासी संपत्ति, धारा 8 का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। घोषित कोई भी संपत्ति होनाः

(प) ऐसी संपत्ति जिसमें विस्थापित व्यक्ति को कोई अधिकार है

(पप) ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हो।

14 अगस्त, 1947,तारीख के बाद एक निर्वासित हस्तांतरण के किसी भी तरीके से, जब तक कि उस हस्तांतरण की धारा 7 के तहत अभिरक्षक द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, यह माना जाएगा कि यह राज्य के अभिरक्षक में निहित हैः

(क) निर्वासित व्यक्ति की संपत्ति के मामले में। धारा एस. सी. आर. के खंड (डी) के उपखंड (आई) में परिभाषित।

जिस तारीख को वह छोड़ता है या किसी स्थान से निकलता है अब भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान के लिए एक राज्य। दिए गए प्रपत्र के साथ पढ़ी जाने वाली नियम की भाषा ऊपर, दावा करने वाले व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस संपत्ति में हित जो, के अनुसार अभिरक्षक के कब्जे में जानकारी है प्रथम दृष्टया निकासी संपत्ति, उसकी सेवा के तरीके और जांच के तरीके से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि धारा 7 का उद्देश्य एक जीवित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना था और उस हद तक परिभाषा में वर्तमान काल का उपयोग करना था।

निर्वासित और निर्वासित संपत्ति का मामला इस तर्क को पुष्ट

करता है कि कार्यवाही का उद्देश्य केवल जीवित व्यक्तियों पर लागू होना है। एक जिसमें एक निर्वासित का कोई अधिकार या हित है लेकिन मृतक को उसकी मृत्यु के बाद कोई अधिकार या हित नहीं है। जैसा कि उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में निहित है। न ही (पप) लागू होता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने हस्तांतरण के किसी भी तरीके से किसी निकासी से संपत्ति प्राप्त नहीं की है। यह स्पष्ट है कि संपत्ति घोषित की जानी चाहिए।

धारा 7 के तहत बेदखल संपत्ति को निहित करने से पहले धारा 8 के तहत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब संपत्ति ऐसा निहित करती है कि निहित करना पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है सकारात्मक रूप से, लेकिन जहाँ आदमी किसी भी ऐसे व्यक्ति से पहले मर जाता है घोषणा की जाती है, संबंध का सिद्धांत-वापस लागू नहीं किया जा सकता है ताकि इस तरह के कानून के संचालन द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों में संपत्ति निहित को प्रभावित किया जा सके। एक सरल उदाहरण लें, यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़ देता है।

1 मार्च, 1947 के बाद दी गई तारीख धारा 2 (डी), और पाकिस्तान में किसी भी पहले मर जाता है धारा 7 के तहत और किसी भी जांच से पहले उसे नोटिस जारी किया गया इसके अनुसरण में

आयोजित किया जाता है, यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी, जो अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, मृतक के अधिकार या हित की जाँच करना हो सकते हैं, ऐसी स्थिति की जांच करके इससे वंचित कर दिया गया संपत्ति में जो पहले से ही कानूनी रूप से हस्तांतरित हो चुकी है उत्तराधिकारी। ऐसे मामले में धारा 8 लागू नहीं होगी और संपत्ति का कोई पूर्वनिर्धारण नहीं हो सकता है।

इस तरह की संपत्ति को खाली करने वाला घोषित करने से पहले धारा 7 और 8 को एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभिरक्षक को घोषणा किए जाने के बाद ही संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। घोषणा धारा 7 के तहत की गई जांच का अनुसरण करती है, लेकिन जब तक धारा 7 के तहत कार्यवाही की जाती है, संपत्ति का कोई निहितकरण नहीं हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप अभिरक्षक को इसका कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब यदि कथित निकासी की घोषणा से पहले मृत्यु हो जाती है, तो संरक्षक को संपत्ति पर कब्जा करने का कोई अधिकार है? यदि वह किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। घोषणा से पहले जीवित व्यक्ति, उसी टोकन से वह कथित निकासी की मृत्यु के बाद कब्जा नहीं ले सकता है जब संपत्ति उत्तराधिकारियों के हाथों में चली गई थी। धारा 7

के तहत जांच धारा 8 के तहत घोषणा करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है और जब तक घोषणा नहीं की जाती है तब तक संपत्ति पर अधिकार का प्रयोग करने का संरक्षक का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि संरक्षक के प्रभुत्व प्राप्त करने से पहले उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति से वंचित किया जाना चाहिए। इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141, जो सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में सभी कार्यवाहियों में लागू होने वाले मुकदमों के संबंध में न्यायालय की प्रक्रिया को लागू करती है, लागू नहीं होती है, क्योंकि अभिरक्षक न्यायालय नहीं है, हालांकि उसके द्वारा आयोजित कार्यवाहियां अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होती हैं। अधिनियम की धारा 45 संहिता के प्रावधानों को केवल किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने और उसकी जांच करने दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में लागू करती है।

प्रतिस्थापन से संबंधित संहिता के प्रावधान, इसलिए, अप्रयोज्य हैं और अधिनियम में मृतक के स्थान पर उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं है ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रखी जा सके। यदि कथित व्यक्ति की मृत्यु

के बाद उत्तराधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।

इसलिए हम मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए।

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक आदमी के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति को निर्वासित संपत्ति घोषित किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रावधान किया गया होता, तो अधिनियम की धारा 8 में अनुध्यात निहित करने से अपने वैधानिक बल द्वारा मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों में मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति निहित करने को विस्थापित कर दिया होता। यह कानून का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रस्ताव है कि एक मृत मुसलमान की संपत्ति उसकी मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारियों को विशिष्ट शेयरों में हस्तांतरित की जाती है, और हस्तांतरण न तो मृतक से देय ऋण के कारण निलंबित किया जाता है, न ही विरासत में मिले शेयरों का वितरण ऋण के भुगतान तक स्थगित किया जाता है। यह भी अच्छी तरह से समझा जाता है कि संपत्ति मुसलमान कानून के तहत उत्तराधिकारियों में निहित होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, एक प्रशासक के हस्तक्षेप के बिना।

अधिनियम की धारा 40 एक प्रतिबंध लगाती है -

14 अगस्त, 1947 के बाद संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए एक निर्वासित का अधिकार। यह धारा अंतर-विवोस हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है लेकिन मृत्यु जैसे कानून के संचालन द्वारा हस्तांतरण को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस धारा के अनुसार जहां किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिसूचित या निर्वासित संपत्ति घोषित किया जाता है, वह 14 अगस्त, 1947 के बाद उस संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, ताकि हस्तांतरणकर्ता पर कोई अधिकार प्राप्त हो सके जब तक कि इसकी पुष्टि संरक्षक द्वारा नहीं की जाती है। इससे पता चलता है कि 1 मार्च और 14 अगस्त, 1947 को एक स्थानांतरण शर्त, के रूप में माने जाने की अक्षमता से मुक्त है।

निकासी संपत्ति इस तथ्य के बावजूद कि स्थानान्तरणकर्ता 1 मार्च के बाद स्थानांतरित हो गया। यदि वह 14 अगस्त, 1947 से पहले अपनी पूरी संपत्ति का प्रामाणिक हस्तांतरण करता है, तो संपत्ति निकासी संपत्ति के रूप में नहीं आती है और इस तरह के हस्तांतरण के लिए अभिरक्षक द्वारा पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि उस तारीख के बाद के सभी हस्तांतरणों को संदिग्ध माना जाता है। यदि दो महत्वपूर्ण तिथियों के बीच स्थानांतरण को वैध माना जाता है, तो तर्क

की समानता पर 14 अगस्त के बाद घोषणा से पहले हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु का परिणाम समान होना चाहिए।

हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम का उद्देश्य एक विशेष तिथि से संपत्ति की प्रकृति तय करना है और यह कि की गई कार्यवाही संपत्ति के खिलाफ है न कि व्यक्ति के खिलाफ। यह तर्क गलत है। कोई संपत्ति, निकासी या अन्यथा नहीं हो सकती है, जब तक कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक न हो। यह मालिक की संपत्ति है जिसे इस तथ्य के कारण निर्वासित संपत्ति घोषित किया जाता है कि वह कुछ आधारों पर विकलांग है। अधिनियम में निकासी संपत्ति की परिभाषा यह कहते हुए शुरू होती है कि ऐसी संपत्ति जिसमें निकासी करने वाले का किसी भी क्षमता में कोई अधिकार या हित हो। अधिनियम यह भी दर्शाता है कि संपत्ति को निकासी संपत्ति के रूप में तब तक अधिसूचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसमें रुचि का दावा करने वाले व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जाता है।

धारा 43 का उल्लेख इस रूप में भी किया जा सकता है कि धारा 8 के तहत कथित निकासी के जीवनकाल के दौरान बनाया जाता था। इस धारा में कहा गया है, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कोई संपत्ति अभिरक्षक के पास निहित है, न तो उसके

बाद किसी भी समय निकासी की मृत्यु, और न ही यह तथ्य कि निकासी जिसका उस संपत्ति में अधिकार या हित था, वह किसी भी भौतिक समय पर निकासी नहीं रह गया था, निहित करने को प्रभावित करेगा या उसके परिणामस्वरूप की गई किसी भी चीज़ को अमान्य कर देगा। खंड से पता चलता है कि जहाँ संपत्ति अभिरक्षक में निहित है, फिर निकासी की मृत्यु या उसके बाद निकासी होने से निहित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसके परिणामस्वरूप कुछ भी वैध नहीं होगा। इस खंड से ऐसा प्रतीत होता है कि कथित निकासी के जीवनकाल में निहित होना चाहिए, अन्यथा यह प्रदान करने का कोई मतलब नहीं था कि खाली कराए गए व्यक्ति की मृत्यु या खाली कराए गए व्यक्ति की मृत्यु से वेस्टिंग प्रभावित नहीं होगी।

सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि धारा 43 इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है कि एक बार जब कोई निकासी हमेशा एक निकासी होती है। यह निष्कर्ष धारा 43 की शर्तों पर शायद ही उचित है जैसा कि ऊपर समझाया गया है और इसे अधिनियम के अन्य प्रावधानों से कोई समर्थन नहीं मिलता है। अधिनियम के उद्देश्य और योजना में कोई संदेह नहीं है

कि अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि इसके शीर्षक से पता चलता है, निकासी संपत्ति के प्रशासन के लिए था और यह सामान्य आधार है कि इस संपत्ति का उपयोग अंततः उन शरणार्थियों को मुआवजा देने के लिए किया जाना है जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी संपत्ति खो दी थी। इस अधिनियम में प्रशासन को कैसे चलाया जाना है, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान हैं।

धारा 9 अभिरक्षक को अधिकार लेने में सक्षम बनाती है।

धारा 8 और धारा 10 के तहत उस में निहित निकासी संपत्ति जो अभिरक्षा की शक्तियों को परिभाषित करती है, आम तौर पर उसे ऐसे उपाय करने में सक्षम बनाती है वह प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है। किसी भी प्रशासन, संरक्षण और प्रबंधन अभिरक्षक को स्थापित करने, बचाव करने या जारी रखने के लिए निर्वासित की ओर से किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही के लिये खड़ा करता है

धारा 15 उस पर मुख्य कार्य करने का दायित्व लगाती है।

धारा 16 अभिरक्षक को पुनर्स्थापित करने का अधिकार देती है निर्वासित को आवेदन करने पर निर्वासित संपत्ति या कोई भी व्यक्ति जो अपने उत्तराधिकारी होने का दावा करता है बशर्ते वह केंद्र सरकार

से एक प्रमाण पत्र देता है कि निर्वासित संपत्ति को उसे बहाल किया जा सकता है। उस पर पुनर्स्थापना संरक्षक सभी से मुक्त हो जाएगा।

इस प्रकार पुनर्स्थापित संपत्ति के संबंध में जिम्मेदारियां डालती है लेकिन इस तरह की बहाली अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, यदि किसी भी, संपत्ति के संबंध में जो किसी अन्य प्रति उस व्यक्ति के खिलाफ बल प्रयोग करने का हकदार हो सकता है जिनका संपत्ति इस तरह पुनर्स्थापित किया गया है।

अधिनियम की धारा 52 के अनुसार यह केंद्र के लिए खुला है।

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी भी पेशेवर को छूट देना। सभी के संचालन से संपत्ति का लाभ या वर्ग या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की।

एस. आर. ओ. 260, दिनांक 3 जुलाई, 1950, जो था भारत के राजपत्र, भाग धारा 3, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 1953, में प्रकाशित दिनांक 15 जुलाई, 1950, पृष्ठ 254, जिसमें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी गई थीः

(क) कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 को या उसके बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन 18 जुलाई से पहले भारत

लौट आया था, और वहाँ बस गए।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो वापसी पर आपत्ति नही प्रमाणपत्र लेकर अस्थायी यात्रा पर पाकिस्तान चला गया है और वापस आ गया है पाकिस्तान (नियंत्रण) अधिनियम, 1949 के तहत जारी एक वैध परमिट के तहत भारत को वापस लौटता है।

(ग) कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से जारी वैध परमिट (स्थायी पुनर्वास के लिए नियंत्रण) अधिनियम, 1949 के तहत पाकिस्तान से 18 अक्टूबर, 1949 से पहले भारत आया है ये प्रावधान यह सुझाव देने से बहुत दूर हैं कि जिस व्यक्ति को निष्क्रमित घोषित किया जाता है उसकी नागरिक मृत्यु का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर सभी समय के लिए एक निकासी को फिर से बनाए रखता है। कुछ परिस्थितियों में उसे बहाल कर दिया जाता है।

कुछ शर्तों के अधीन और पूर्वाग्रह के बिना मूल स्थिति और उसकी संपत्ति उसे बहाल कर दी जाती है संपत्ति के संबंध में अधिकार, यदि कोई हों, जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध लागू करने का हकदार हो सकता है।

ये प्रावधान यह भी स्थापित करते हैं कि सम्पत्ति का निकासी संपत्ति होना स्थायी गुण नहीं है और दी गई शर्तों के तहत ऐसा होना

बंद हो सकता है। संपत्ति किसी भी अंतर्निहित दुर्बलता से पीड़ित नही होती है। बल्कि मालिक से जुडी अक्षमता के कारण विस्थापित संपत्ति बन जीती है। एक बार जब वह विकलांगता समाप्त हो जाती है, तो संपत्ति उस अक्षमता से मुक्त हो जाती है और मालिक को बहाल करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है।याचिकाकर्ता के वकील श्री देसाई ने दलीलों के दौरान प्रेसीडेन्सी टाउन दिवाला अधिनियम की धारा 93 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 17 का उल्लेख किया।

पूर्व के अनुसार यदि कोई ऋणी जिसके द्वारा या उसके खिलाफ दिवालिया याचिका प्रस्तुत की गई है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश नहीं देता है, कार्यवाही ऐसे जारी रखी जाएगी जैसे कि वह जीवित था। उत्तरवर्ती धारा द्वारा यदि कोई ऋणी जिसके द्वारा या उसके विरुद्ध दिवालिया याचिका प्रस्तुत की गई है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मामले में कार्यवाही, जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश नहीं देता है, तब तक जारी रखी जाएगी जहां तक ऋणी की संपत्ति की वसूली और वितरण के लिए आवश्यक हो। हालाँकि इन दोनों धाराओं की भाषा में थोड़ा अंतर है, लेकिन ऋण शोधन विधि में अंतर्निहित सिद्धांत से यह प्रतीत होता है कि ऋण लेने वालों की मृत्यु हो गई है तो कार्यवाही समाप्त नही होती लेकिन

उन्हें जारी रखा जाना चाहिए ताकि उसकी संपत्ति को लेनदारों के लाभ के लिए प्रशासित किया जा सके। हमारे समक्ष अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि विधायिका का इरादा धारा 7 के तहत कार्रवाई के प्रयोजन हेतु व्यक्ति को उनकी मृत्यु के बाद भी, कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए जीवित मानना था। इस तरह के प्रावधान अधिनियम में शामिल किए गए हैं।

मामले पर अपना सर्वश्रेष्ठ विचार करने के बाद हमारी राय है कि कस्टोडियन जनरल द्वारा पारित 30 जुलाई, 1951 का आदेश जिसमें मृतक अबुबकर अब्दुल रहमान को निष्क्रांत घोषित किया गया था और उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को विस्थापित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था, खड़ा नहीं हो सकता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए। हम तदनुसार 1952 की याचिका संख्या 105 से उत्पन्न 1953 की अपील संख्या 65 को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि संरक्षक जनरल को 30 जुलाई, 1951 का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। और इसे रद्द करते हैं। हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

1952 की याचिका सं. 106 को प्रेस नहीं किया गया है और न इसके संबंध में आदेश पारित किया जाना चाहिए। 1953 की अपील सं.

65 में हमारे आदेश को ध्यान में रखते हुए, 1952 की याचिका सं. 247 में कोई आदेश नहीं मांगा गया है।

अपील की अनुमति दी गई।

अपीलार्थियों और याचिकाकर्ताओं के लिए अभिकर्ताः राजिंदर नारायण।

याचिका संख्या 247 में प्रत्यर्थी के लिए अभिकर्ता; जी. एच. राजाध्यक्ष।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता राणावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।